

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI  
TUESDAY, JUNE 7, 2022

## Residents go to MLA over DDA's changes to Deer Park green belt

TIMES NEWS NETWORK

**New Delhi:** Residents of Safdarjung and Green Park have approached government officials and written to their area MLA claiming that 'improper management' and alterations carried out by DDA at Deer Park and City Park at Hauz Khas Village are changing the nature of one of the last green belts in the city.

More than 175 residents have signed a letter, with photographs attached, pointing to several incidents of tree felling and picnic huts being converted into offices. Residents said despite several attempts, they failed to reach the officials.

A spot visit revealed that the picnic huts have been removed and a DDA office has come up in their place.

When contacted, a DDA official said on the condition of anonymity, "There were four huts or cabins earlier for public use, and mostly couples used to book them. The existing DDA office was constructed over two of the huts about three years ago. We have now deci-



**UNDER THREAT?** More than 175 residents have signed a letter, with photographs attached, pointing to several incidents of tree felling and picnic huts being converted into offices

ded to use the third hut as well for office use."

Asked about felling of trees, the official said some large branches of the canopy trees were pruned to avoid accidents.

The residents, however, alleged that "large parcels of the land are being taken over and used for other activities".

"The picnic hut, designated as such in the Master Plan, is being used as an offi-

ce. This is not appropriate. People have the right to use the space for a picnic, as it is not possible to have one out on the grass due to the presence of monkeys," said Sagri Chhabra, who led the residents' petition.

She also claimed attempts are being made to convert Deer Park into a zoo.

"Since the 70s, the park has been home to the deer and that is how it gets its na-

### Times View

Delhi is tormented by pollution. The green zones act as its lungs allowing the city to breathe better. They must be preserved and protected. It is a matter of serious concern that parts of the green belt are being encroached. The problem must be nipped in the bud.

me. Why is there a move to call it the AN Jha Mini Zoo now? A zoo entails ticketing and possible placement of other animals. This could change the character of the park, which is a wilderness zone and one of Delhi's last green belts," the residents said in their complaint.

They added that several manmade structures, such as fountains, have come up near Hauz Khas lake, adjacent to Deer Park.

"There are enclosures made of plastic and the park staff put food for the ducks. The lake should be a living lake and filled with fishes. Let the ducks find their own food," said the application.

## LG is crossing boundaries, says AAP MLA; BJP hits back

**New Delhi:** Aam Aadmi Party MLA Somnath Bharti on Monday alleged that Delhi lieutenant governor Vinai Kumar Saxena is crossing constitutional boundaries by claiming that not just DDA and Delhi Police, but the whole of Delhi is under his control.

Bharti said in a press conference that a delegation of nine AAP MLAs met Saxena and appealed to him to not interfere with the elected government's work. "Delhi LG is refusing to fall in line and has expressed his desire to continue infringing upon the Kejriwal government's powers," he alleged. "The attitude and body language of the LG makes it clear that he wishes to meddle with the work that people of Delhi chose the CM to do," he said.

"The condition of DDA, Delhi Police, and MCD is extremely poor, and we hope that the new LG will work towards improving it," he said, adding that as per the Constitution, matters relating to land, police, and law and order in Delhi fall under the LG's purview, while all other departments come under the jurisdiction of Delhi's elected government.

While the LG secretariat did not respond to the allegations, Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor said, "Even in most matters where the Delhi government can take decisions constitutionally, it is mandatory for the government to take prior approval or ultimate consent of the LG." TNN

### दैनिक जागरण

## सरकार और एलजी के बीच टकराव बढ़ने की आशंका

राज्य व्यूरे, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार और राजनिवास के बीच टकराव बढ़ने की आशंका नजर आने लगी है। दिल्ली के कामकाज को लेकर सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दल ने एलजी से मुलाकात की। आप नेताओं का कहना है कि मुलाकात के दौरान उपराज्यपाल (एलजी) ने कहा कि डीडीए और पुलिस ही नहीं, पूरी दिल्ली हमारी है। आप ने इसे दिल्ली सरकार के कामकाज में दखलंदाजी माना है। आप के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि ऐसा लगता है कि एलजी की मंशा सोएएम के काम में दखल देने की है।

भारती ने कहा कि दिल्ली में डीडीए, दिल्ली पुलिस और एमसीडी के हालात सबसे खराब हैं। उम्मीद है कि एलजी इनकी बदहाली दूर करने

● आप का दावा, मिलने गए विधायकों से एलजी ने कहा- डीडीए व पुलिस ही नहीं, पूरी दिल्ली हमारी

पर ध्यान देंगे। संविधान में एलजी और मुख्यमंत्री के बीच अधिकारों को लेकर लाइन खींची गई है, उम्मीद है कि वह उसके अनुरूप भी काम करेंगे। बता दें कि सोमवार को आप के नौ सदस्यीय विधायक दल ने एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारती ने कानून व्यवस्था और डीडीए के संबंध में एलजी का ध्यान आकर्षित किया कि यहां कानून व्यवस्था को लेकर लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। आप सरकार की ओर से डीडीए के पास जितनी भी रिक्वेस्ट गई, एक भी पूरी नहीं हुई।

भारती के अनुसार उन्होंने एलजी

● उपराज्यपाल के इस बयान को दिल्ली सरकार के कामकाज में दखलंदाजी मान रही आप

से कहा कि मैं खुद डीडीए का मेंबर रह चुका हूँ। हमने मोहल्ला क्लिनिक के साथ कई अन्य कार्यक्रमों के लिए जमीन मांगी, पर नहीं मिली। नगर निगम का जो चुनाव अप्रैल में होना था, उसे असंवैधानिक तरीके से निरस्त कर वहां का कंट्रोल भाजपा की केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। विधायकों ने इस बात का भी उल्लेख किया कि किस प्रकार निगम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। उनके अनुसार, लेकिन एलजी ने कहा कि तीन क्षेत्र ही हमारे पास नहीं हैं, बल्कि पूरी दिल्ली हमारी है। इस दौरान विधायक प्रवीण कुमार,

अजय दत्त, एसके बग्गा, मदन लाल आदि भी मौजूद थे।

मनीष सिसोदिया ने की उपराज्यपाल से मुलाकात : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। राजनिवास में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों ने दिल्ली के विकास पर बात की। इसकी जानकारी स्वयं एलजी ने ट्वीट कर साझा की। उन्होंने कहा कि आज उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। इस दौरान हमने दिल्ली के विकास और लोगों के कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की है। इससे पहले सोएएम अरविंद केजरीवाल भी एलजी से मुलाकात कर चुके हैं। इसमें पानी, विकास व अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है।



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS \_\_\_\_\_

DATED \_\_\_\_\_

**हिन्दुस्तान**

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | मंगलवार, 7 जून 2022

त विहा

## सात साल में दस नोटिस, जमीन किसकी है पता नहीं

**केस 3**

वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे लाइन किनारे ग्रीन पार्क की दीवार गिर गई।

यह घटना 22 फरवरी 2015 की है। इसमें दो किशोर गंभीर रूप से घायल हो गये। बाद में इलाज के दौरान 15 वर्षीय अनूप ने दम तोड़ दिया।

**लापरवाही में दर्ज किया गया था मामला :** अशोक विहार थाने में लापरवाही से मौत की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। प्राथमिक जांच में यह जमीन डीडीए की मिली, तो जांच अधिकारी ने संबंधित कार्यकारी अभियंता को नोटिस देकर पूछा कि इसके रखरखाव की जिम्मेदारी किस

- रेलवे लाइन किनारे ग्रीन पार्क की दीवार गिर गई थी
- इलाज के दौरान पीड़ित ने दम तोड़ दिया था

अधिकारी की थी। डीडीए ने घटना से पहले जमीन रेलवे को देने की बात कही। पुलिस ने संबंधित रेलवे अभियंता को नोटिस दिया, लेकिन उसने घटना के बाद जमीन का मालिकाना हक मिलने की बात कही। पुलिस ने दोनों अभियंताओं को एक साथ नोटिस दिया। इस तरह सात साल में विभिन्न जांच अधिकारियों ने 10 नोटिस दोनों विभागों को दिए, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जमीन किसकी है। इस वजह से संबंधित अधिकारी की

जिम्मेदारी तय कर उसे आरोपी भी नहीं बनाया जा सका। फिर जांच अधिकारी ने बीते साल क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी।

जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश : अदालत ने जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। वहीं, घटना के चार साल बाद जांच से निराश होकर मृतक के परिजन भी दिल्ली छोड़कर अपने पैतृक गांव चले गए।

## एलजी की सीएम के कामों में दखल देने की मंशा : आप

■ **विस, नई दिल्ली :** दिल्ली के नए उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से सोमवार को औपचारिक भेंट करने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने गंभीर आरोप लगाए। पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक सोमनाथ भारती ने दावा किया कि नए उप-राज्यपाल ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के कामों में दखल देने की मंशा जाहिर करते हुए हमसे कहा है कि डीडीए और पुलिस ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली हमारी है।

सोमनाथ भारती ने कहा कि उप-राज्यपाल का बर्ताव और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर यह साफ हो गया है कि सीएम के अधिकारों में हस्तक्षेप करने की उनकी तमन्ना है। संविधान में उप-राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अधिकारों को लेकर जो लाइन खींची गई है, हम उम्मीद करते हैं कि एलजी उसके अनुरूप काम करेंगे।

## एलजी हस्तक्षेप करना चाहते हैं : सोमनाथ भारती

नई दिल्ली। आप विधायक सोमनाथ भारती का आरोप है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री के कामों में दखल देने की मंशा जाहिर की है। उनके मुताबिक एलजी ने कहा कि डीडीए और पुलिस ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली हमारी है। यह आरोप सोमवार को उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद लगाया है। सोमनाथ भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री के अधिकार में वह हस्तक्षेप करना चाहते हैं।

**Hindustan Times**

## DDA reopens land pooling bookings

**NEW DELHI:** Months after the Centre proposed amendments in the land pooling policy, the Delhi Development Authority (DDA) has once again opened registrations for land owners to participate in the policy that is aimed at meeting the Capital's housing requirement. A senior DDA official said, "The registration will now be open till August 25. The DDA recently issued provisional notice for formation of consortiums in three sectors north Delhi's Bawana, Tigipur, Fatehpur Jat etc. The land owners have to form the consortiums by August end."

The land pooling policy was first notified in 2013 and later in 2018 to meet the increasing demand for housing in Delhi. The policy will be implemented in 110 urbanised villages. But the policy is yet to be operationalised due to a clause as per which 70% contiguous land is essential. DDA has

been struggle to meet this criterion, as some land owners are not willing to participate in it or have not registered so far

DDA officials said the registrations were opened to allow land owners in three sectors, where permission to form consortiums was given recently, to participate and meet the 70% contiguous land requirement to operationalise the policy. The DDA is also working on amending the Delhi Development Act, 1957, for swift implementation of the policy. According to the proposed amendment, it will be mandatory for land owners to participate in the land pooling policy in sectors wherein minimum threshold for participation has been achieved. The three sectors include villages in north and northwest Delhi. "In all the sectors, we have got land but it is not contiguous," said a DDA official.

HTC



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

DELHI THE HINDU

NAME OF NEWSPAPERS- TUESDAY, JUNE 7, 2022

DATED

## Tussle between AAP and L-G intensifies over issue of powers

Row over Saxena's purported statement that 'entire' Delhi is under his control

STAFF REPORTER  
NEW DELHI

The tussle between the Aam Aadmi Party (AAP) and Vinai Kumar Saxena intensified on Monday after a delegation of nine party MLAs called on the newly appointed Lieutenant-Governor.

After meeting Mr. Saxena, the MLAs, including Somnath Bharti, former Delhi Minister, alleged that the L-G told them that not just the Delhi Development Authority and the Delhi police, but the "whole of Delhi" was under his control.

Mr. Bharti said that L-G made this statement when the AAP MLAs raised several issues before him including some pertaining to law and order.

When contacted, the L-G's office did not offer any comment.

### Growing rift

Over the past few days, AAP leaders have on several occasions accused Mr. Saxena of overstretching his Constitutional powers and encroaching upon those of the Government of the National Capital Territory of Delhi.

The L-G's office all this while refused to be drawn into a public spat with the elected government, citing norms of office.



AAP MLA Somnath Bharti alleged that the L-G told them that not just the Delhi Development Authority and Delhi police, but the "whole of Delhi" is under his control. ■ FILE PHOTO

Speaking about his meeting with the L-G, Mr. Bharti said, "The L-G is refusing to fall in line and has expressed his desire to continue infringing upon the Delhi government's powers."

Praveen Kumar, another AAP MLA, who was part of the delegation, said Mr. Saxena told them that he was well aware of his powers in Delhi and did not need the MLAs to remind him of his authority.

### The backdrop

When Mr. Saxena was appointed last month, the AAP chief Arvind Kejriwal tweeted, "On behalf of the people of Delhi, I extend a warm welcome to the newly appointed Lieutenant Governor of Delhi, Mr. Vinai Ku-

mar Saxena. For the betterment of Delhi, he will get full cooperation from the Cabinet of Delhi Government."

However, the period of calm was short-lived.

On June 1, AAP took the first potshot at the L-G and accused him of attacking "Delhi's constitutional sanctity" and appealed to him to not disrupt Delhi's constitutional framework.

AAP's attack was triggered by a meeting that the L-G had called of the officials of the Delhi Jal Board.

On Sunday the party questioned Mr. Saxena's "silence" on "the deteriorating law and order situation in the Capital".

Mr. Bharti said, "We reiterated that the departments

which come directly under the L-G's purview are plagued with endless problems. However, it is with a heavy heart that I say this, on behalf of all my colleagues, that the L-G Shri Vinai Kumar Saxena claimed that he has the authority over the entire Capital."

### BJP's response

Reacting to the AAP MLAs' statements, Delhi Bharatiya Janata Party (BJP) spokesperson Praveen Shankar Kapoor said AAP needed to stop spreading "lies" that Mr. Saxena could only take up matters of services, land and order.

"Even in most matters where the Delhi government can take decisions it is mandatory according to the constitution for the government to take prior approval or ultimate consent of the L-G," Mr. Kapoor said.

He added, "Moreover, in public welfare matters and in cases where complaints of corruption or of non-performance are concerned, the L-G is fully empowered to attend and inspect."

Despite the deepening discord between them, Mr. Saxena and Mr. Kejriwal have vouched for "better coordination" to effectively address the city's issues.



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost

NAME OF NEWSPAPERS--

NEW DELHI | TUESDAY, 7 JUNE, 2022 ED-----

NO PROGRESS ON THE IDEA, OFFICIALS SAY IT IS UNLIKELY TO BECOME A REALITY

## 2 years on, no 'land bank' for compensatory plantation

OUR CORRESPONDENT

**NEW DELHI:** Nearly two years after the Delhi Forest Department asked land-owning agencies to create a "land bank" for compensatory plantation of trees in the capital, no progress has been made on the idea and officials say it is unlikely to become a reality.

In mid-2020, the Forest Department had asked the Delhi Development Authority (DDA) and the development commissioner to create a pool of vacant plots to simplify and expedite the process of compensatory plantation.

"With the creation of a land bank, the DDA will not have to

identify new land every time a project proposal comes up and agencies could approach the forest department directly," an official said.

Agencies undertaking developmental projects approach the DDA seeking land for compensatory plantations for trees felled for their projects.

At multiple meetings, the DDA told the Forest Department it does not have land for compensatory plantation or afforestation and the few small parcels it has have already been committed for developmental projects.

"Since we do not have land for plantation, there is no question of a land bank now," a

senior DDA official said.

With the problem of land shortage aggravating over the years, the DDA got compensatory plantation done in parks in some cases, the official shared.

Under the Master Plan of Delhi, it had been decided to set aside 15 per cent of the area for recreational land use under which all parks, greenbelts and forests are maintained.

"Against the 15 per cent area identified for recreational green use, the total forest and tree cover in the capital is now over 23 per cent as per the latest State of Forest Report published by the Forest Survey of India, Dehradun," the official said. "Most of the recreational

green areas identified under the master plan are already saturated with plantations... Other vacant land parcels available in small patches are required for basic developmental needs of the citizens of Delhi," he said.

Citing a shortage of land in Delhi, the DDA had recently requested the Forest Department to revise the compensatory plantation scheme guidelines and bring down the number of saplings to be planted for every tree felled from 10 to two.

The Delhi government, however, rejected the request and set up a nine-member committee to suggest alternatives to overcome the shortage of land for tree plantation in the city. It also

asked the DDA to inform how much land is available for plantation in the capital.

The DDA also wrote to the Union Environment Ministry, requesting it to allow compensatory afforestation in neighbouring states for all projects undertaken in Delhi in view of the scarcity of land in the capital.

The agency said the ministry should at least relax the guidelines issued under the Forest Conservation Act to allow compensatory afforestation for the projects implemented by the central government and public sector undertakings on degraded forest land in the neighbouring states.

## As tussle between Delhi govt & L-G continues, AAP MLAs meet Saxena

OUR CORRESPONDENT

**NEW DELHI:** A group of Aam Aadmi Party MLAs called on Delhi LG Vinai Kumar Saxena on Monday, a meeting that comes against the backdrop of the ruling party's mounting accusations of interference by him in the government's work.

Somnath Bharti, one of the members of the delegation while addressing a press conference yesterday claimed that the L-G has refused to fall in line and wishes to continue infringing upon the Kejriwal government's powers. He said, "The L-G is crossing constitutional boundaries by claiming that not

just DDA and Delhi Police, but the whole of Delhi is under his control. The attitude and body language of BJP-led Centre's nominated LG makes it clear that he wishes to meddle with the work that people of Delhi chose CM Kejriwal to do."

Bharti further added that the delegation made it clear to the L-G that as per the constitution matters related to land, police, and law & order in Delhi fall under him. The delegation also raised issues regarding Delhi's law & order situation, DDA related problems, and other matters in front of L-G.

The delegation further raised concerns about the

delay in MCD elections and how there has been negligence in services that the MCD is responsible for.

The AAP had last week accused the L-G of meddling in the affairs of the government and not focussing on the areas under his control.

"Members of the Delhi Legislative Assembly called on today. We discussed various issues pertaining to the City and their constituencies," Saxena said in a tweet.

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia also met L-G Saxena on Monday amid allegations of interference by him in the government's work.

पंजाब केसरी

## 'आप' के 9 विधायक ने की उपराज्यपाल से मुलाकात



नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से आम आदमी पार्टी के 9 विधायकों ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि डीडीए और पुलिस ही नहीं, पूरी दिल्ली हमारी है। इस पर विधायक सोमनाथ भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार के उपराज्यपाल का एटीट्यूड, बाँडो लैंग्वेज से साफ हो गया कि जो अधिकार दिल्लीवासियों ने सीएम

अरविंद केजरीवाल को सौंपे हैं, उसमें हस्तक्षेप करने की उनकी तमन्ना है। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि जमीन, कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस के अलावा सभी विषय मुख्यमंत्री के अंतर्गत आएं, उसके बावजूद भी उपराज्यपाल का कहना कि पूरी दिल्ली मेरे पास है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में डीडीए, दिल्ली पुलिस और एमसीडी के हालात बेहद खराब हैं। इस दौरान विधायक प्रवीण, अजय दत्त, एसके बग्गा, मदन लाल सहित अन्य मौजूद रहे।